

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 14, शुक्रवार, शके 1945-अक्टूबर 06, 2023 <i>Asvina 14, Friday, Saka 1945- October 06, 2023</i>	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये
सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 28, 2023

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/विनियम/149:- विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वां) की धारा 61, 66, 86 (1)(ई) सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित अक्षय ऊर्जा उत्पादन प्रणालीयों के लिये एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1 लघु शीर्षक, प्रारम्भण तथा प्रयोज्यता की सीमा:

- (1) ये विनियम, “राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड पारस्परिक क्रिया वितरित अक्षय ऊर्जा उत्पादन तंत्र) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023” कहलायेंगे।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. विनियम 6 में संशोधन

विद्यमान उप-विनियम 6.1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“6.1 किसी ट्रांसफार्मर विशेष पर अक्षय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली की संचयी क्षमता ऐसे वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता के 80 प्रतिशत या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित की जाने वाली ऐसी सीमा से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते यह कि यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर के संवर्द्धन की आवश्यकता हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह अपनी लागत पर ऐसा किया जायेगा।

बशर्ते यह भी कि उच्च आतिति उपभोक्ताओं के मामलों में, जहां पर वितरण ट्रांसफार्मर उपभोक्ता द्वारा अधिष्ठापित किया गया है, 80 प्रतिशत वितरण ट्रांसफार्मर

क्षमता की सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ताओं के लिये कुल स्वीकार्य स्थापना क्षमता इन विनियमों के विनियम 7.2 के अनुसार होगी।”

3. विनियम 10 में संशोधन

विद्यमान उप-विनियम 10.14.3 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“उपभोक्ता के मीटर के पीछे स्थापित अक्षय ऊर्जा उत्पादन तंत्र की अधिकतम ए.सी. क्षमता (ए.सी. की ओर इन्वर्टर क्षमता) उपरोक्त विनियम 10.14.2 के अंतर्गत अनुमत क्षमता से अधिक नहीं होगी। यदि किसी भी समय-ब्लॉक के दौरान, अधिकतम ए.सी. क्षमता उपरोक्त अनुमत क्षमता से अधिक हो जाती है तो 15-मिनट या 30-मिनट ब्लॉक, जो लागू हो, के तत्समान अतिरिक्त उत्पादन को डिस्कॉम से यथा विचारा गया आहरण के व्यवहृत किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: स्थापित डीसी क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।”

4. विनियम 12 में संशोधन

(1) विद्यमान उप-विनियम 12.5.2 के मुख्य प्रावधान और प्रथम परन्तुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“12.5.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारी पिछले वित्तीय वर्ष में संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से ज्ञात किये गए और आयोग द्वारा अंगीकृत भारित औसत टैरिफ से 40 प्रतिशत अधिक के प्रोत्साहन पर कनेक्शन समझौता करेगा। यदि पिछले वित्तीय वर्ष में कोई बोली प्रक्रिया नहीं की गयी है, तो प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ज्ञात किये गए नवीनतम टैरिफ से 40 प्रतिशत अधिक का प्रोत्साहन लागू होगा:

बशर्ते यह कि यदि संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए कोई बोली प्रक्रिया नहीं की गयी है, तो प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ज्ञात किये गए और आयोग द्वारा अंगीकृत 5 मेगावाट और अधिक की बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के नवीनतम भारित औसत टैरिफ से 40 प्रतिशत अधिक का प्रोत्साहन लागू होगा:”

(2) विद्यमान उप-विनियम 12.5.6 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“12.5.6 नेट बिलिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित अक्षय ऊर्जा उत्पादन तंत्र की अधिकतम ए.सी. क्षमता (ए.सी. की ओर इन्वर्टर क्षमता) अनुबन्धित ए.सी. क्षमता से अधिक नहीं होगी। यदि किसी भी समय-ब्लॉक के दौरान यदि अधिकतम ए.सी. क्षमता अनुबन्धित ए.सी. क्षमता से अधिक हो

जाती है, तो 15-मिनट या 30-मिनट ब्लॉक, जो लागू हो, का तत्समान अतिरिक्त उत्पादन व्यतीत हो जायेगा।

स्पष्टीकरण: स्थापित डीसी क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।”

- (3) विद्यमान उप-विनियम 12.6.1 (क) के मुख्य प्रावधान और प्रथम परन्तुक एवं उप-विनियम 12.6.1 (घ) के मुख्य प्रावधान को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“क) यदि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता द्वारा निर्यात की जाने वाली विद्युत की मात्रा बिलिंग अवधि के दौरान आयात की गई मात्रा से अधिक है, तो ऐसे घरेलू उपभोक्ता द्वारा निर्यात की जाने वाली अतिरिक्त मात्रा को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 5 मेगावाट और उससे अधिक की वृहद सौर परियोजनाओं के भारित औसत टैरिफ, जिसे पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ज्ञात किया गया था, और आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया था से 25 प्रतिशत अधिक पर क्रय किया जाएगा। यदि पिछले वित्तीय वर्ष में कोई बोली प्रक्रिया नहीं की गई है, तो प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ज्ञात नवीनतम टैरिफ से 25 प्रतिशत अधिक लागू होगा। ऐसे उपभोक्ता द्वारा अंतःक्षेप की गई अतिरिक्त ऊर्जा के लिए प्राप्त कुल राशि को क्रेडिट के रूप में समायोजित किया जाएगा, जो तुरंत उतरवर्ती बिलिंग चक्र में देय ऐसी राशि के बराबर है:

बशर्ते कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (रूफटॉप तथा लघु सौर ग्रिड पारस्परिक क्रिया तन्त्र हेतु संयोजिता तथा नेट मीटरिंग) विनियम, 2015 और उसके पश्चातवर्ती संशोधनों के अनुसार शासित विद्यमान नेट मीटरिंग संस्थापन वाले घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में भी, निर्यात की गयी अतिरिक्त मात्रा को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 5 मेगावाट और उससे अधिक की वृहद सौर परियोजनाओं के भारित औसत टैरिफ, जिसे पिछले वित्तीय वर्ष में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ज्ञात किया गया था, और आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया था से 25 प्रतिशत अधिक पर क्रय किया जाएगा। यदि पिछले वित्तीय वर्ष में कोई बोली प्रक्रिया नहीं की गई है, तो प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ज्ञात नवीनतम टैरिफ से 25 प्रतिशत अधिक लागू होगा। ऐसे उपभोक्ता द्वारा अंतःक्षेप की गई अतिरिक्त ऊर्जा के लिए प्राप्त कुल राशि को क्रेडिट के रूप में समायोजित किया जाएगा, जो तुरंत उतरवर्ती बिलिंग चक्र में देय ऐसी राशि के बराबर होगी:”

- घ) “नेट बिलिंग व्यवस्था के अंतर्गत स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र की अधिकतम ए.सी. क्षमता (ए.सी. की ओर इन्वर्टर क्षमता) अनुबन्धित ए.सी. क्षमता से अधिक नहीं होगी। यदि किसी भी समय-ब्लॉक के दौरान यदि अधिकतम ए.सी. क्षमता अनुबन्धित ए.सी. क्षमता से अधिक हो जाती

है, तो 15-मिनट या 30-मिनट ब्लॉक, जो लागू हो, का तत्समान अतिरिक्त उत्पादन व्यतीत हो जायेगा।

स्पष्टीकरण: स्थापित डीसी क्षमता पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।”

- (4) उप-विनियम 12.6.1(ख) के विद्यमान प्रथम परन्तुक को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“बशर्ते यह कि नेट मीटरिंग उपभोक्ताओं के लिये ग्रिड से सभी स्रोतों से शुद्ध आयातित ऊर्जा (कुल उपभोग - स्वीकार्य सौर उत्पादन) की बिलिंग सभी स्रोतों से कुल उपभोग के अनुरूप लागू स्लैब के अनुसार की जायेगी।”

5. विनियम 15 में संशोधन

विद्यमान मुख्य उप-विनियम 15.2 के नीचे निम्नानुसार नया तृतीय परन्तुक जोड़ा जायेगा:

“बशर्ते यह भी कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं, राज्य सरकार के भवन, स्थानीय निकाय और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के लिये नेट मीटरिंग-व्यवस्था के अंतर्गत रेस्को (आरईएससीओ) के स्वामित्व वाली नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन प्रणाली के लिए कोई क्रॉस सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार लागू नहीं होगा।”

आयोग की आज्ञा से,

हिमांशु खुराना,
सचिव।

Rajasthan Electricity Regulatory Commission Notification Jaipur, August 28, 2023

No. RERC/Secy./Reg./149 - In exercise of powers conferred under Section 181 read with Sections 61, 66, 86(1)(e) of the Electricity Act, 2003 (Act 36 of 2003) and all other provisions enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission after previous publication, hereby makes the following Regulations for Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems:

1. Short title, commencement and extent of application:

- (1) These Regulations may be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Grid Interactive Distributed Renewable Energy Generating Systems) (First Amendment) Regulations, 2023.
- (2) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment in Regulation 6:

The existing sub-regulation 6.1 shall be substituted with the following:

"6.1 The cumulative capacity of Renewable Energy generating system to be allowed at a particular distribution transformer shall not exceed 80% of the capacity of such distribution transformer or such limit as may be stipulated by the Commission from time to time:

Provided that in case augmentation of transformer installed by the Distribution Licensee is required the same shall be done by the Distribution Licensee at its own cost.

Provided further that, in case of HT consumers where the distribution transformer has been installed by the consumer, the limit of 80% of distribution transformer capacity shall not be applicable. The total allowable solar installation capacity for such consumers shall be as per Regulation 7.2 of these Regulations."

3. Amendment in Regulation 10:

The existing sub-regulation 10.14.3 shall be substituted with the following:

"The peak AC capacity (inverter capacity on AC side) of the Renewable Energy generating station installed behind Consumer's meter shall not exceed the capacity permissible under regulation 10.14.2 above. In case during any time block, if the peak AC capacity exceeds the above permissible capacity the corresponding excess generation of 15-Minute or 30-Minute block, as applicable shall be treated as deemed drawl from the Discom."

Explanation: There shall be no restriction on installed DC capacity.

4. Amendment in Regulation 12:

- (1) The existing main provision and first proviso of sub-regulation 12.5.2 shall be substituted with the following:

"12.5.2 The Distribution Licensee shall enter into Connection Agreement at the weighted average tariff discovered through Competitive Bidding for respective technology in previous Financial Year and adopted by the Commission plus an incentive of 40%. In case no bidding is done in previous Financial Year, then the latest tariff discovered through competitive bidding plus an incentive of 40% shall be applicable:

Provided that, in case no bidding is done for respective technology, the latest weighted average tariff of large-scale solar projects of 5 MW and more, discovered through Competitive Bidding and adopted by the Commission, plus an incentive of 40% shall be applicable."

- (2) The existing provision of sub-regulation 12.5.6 shall be substituted with the

following:

“12.5.6 The peak AC capacity (inverter capacity on AC side) of the Renewable Energy generating station installed under the Net Billing arrangement shall not exceed the contracted AC capacity. In case during any time block, if the peak AC capacity exceeds the contracted AC capacity the corresponding excess generation of 15-Minute or 30-Minute block, as applicable shall lapse.

Explanation: There shall be no restriction on installed DC capacity.”

(3) The existing main provisions and first proviso of sub-regulation 12.6.1 (a) and the existing main provision of 12.6.1 (d) shall be substituted with the following:

“a) If the quantum of electricity exported by a domestic category consumer exceeds the quantum imported during the Billing Period, the excess quantum exported by such domestic consumer shall be purchased by the Distribution Licensee at the weighted average tariff of large-scale solar projects of 5 MW and more, discovered through Competitive Bidding in last Financial Year, and adopted by the Commission plus 25%. In case no bidding is done in previous Financial Year, then the latest tariff discovered through competitive bidding plus 25% shall be applicable. The total amount arrived for excess energy injected by such consumer shall be adjusted in the form of credit equivalent to such amount payable in the immediately succeeding billing cycle.”

Provided that, even in case of Domestic consumers having existing Net Metering installations governed as per the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Connectivity and Net Metering for Rooftop and Small Solar Grid Interactive Systems) Regulations, 2015 and subsequent amendments thereof, the excess quantum exported shall be purchased by the Distribution Licensee at the weighted average tariff of large scale solar projects of 5 MW and more, discovered through Competitive Bidding in last Financial Year, and adopted by the Commission plus 25%. In case no bidding is done in previous Financial Year, then the latest tariff discovered through competitive bidding plus 25% shall be applicable. The total amount arrived for excess energy injected shall be adjusted in the form of credit equivalent to such amount payable in the immediately succeeding billing cycle.”

“d) The peak AC capacity (inverter capacity on AC side) of the Renewable Energy generating station installed under the Net Metering arrangement shall not exceed the contracted AC capacity. In case during any time block, if the peak AC capacity exceeds the contracted AC capacity the corresponding excess generation of 15-Minute or 30-Minute block, as applicable shall lapse.

Explanation: There shall be no restriction on installed DC capacity.”

(4) The existing First Proviso to sub-regulation 12.6.1 (b) shall be substituted with the

following:

“Provided that, for Net Metering consumers the Net imported energy (Total Consumption from all sources- Allowable Solar Generation) from the grid shall be billed according to the applicable slab corresponding to the total consumption from all sources.”

5. Amendment in Regulation 15:

A new Third proviso shall be added below the existing main sub-regulation 15.2 as under:

“Provided also that no cross-subsidy surcharge and additional surcharge shall be applicable for RESCO-owned Renewable energy generating system under Net-Metering arrangement setup for domestic category consumers, State Govt. buildings, local bodies and public undertakings of the State Govt.”

By Order of the Commission,

Himanshu Khurana,
Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।